प्राकृतिक आपदाओं के कारण बारंबार होने वाली क्षति

*325. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव: †

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं से लाखों/करोड़ों के जन-धन की भारी क्षति होती है और हमारे देश को अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आग और बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन की क्षति को बचाने के लिए इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करके उपाय ढूंढने हेतु विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के विभिन्न भागों में जन हानि होती है और सम्पत्ति को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है जो आपदा की प्रबलता पर निर्भर करती है।

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों तथा संस्थानों जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, अन्तरिक्ष विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान तथा भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के बहुत से वैज्ञानिक तथा परिष्कृत नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसे उपायों का पता लगाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़, चक्रवात आदि के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। भारत सरकार आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने और आपदा के दुष्प्रभावों को कम करने से संबंधित कार्यकलापों के विषय में लोगों को जागरूक बनाने और उनकी प्रभावी सहभागिता को भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दे रही है।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर सभापति जी, प्रतिवर्ष बाढ़, भारी बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, भूकम्प और समुद्री तूफान, आदि से देश में धन जन की अपार क्षति होती है। इस बात को माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग "ख" के उत्तर में स्वीकार भी किया है और यह बात सही भी है। मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि इस देश में जो दैवी आपदा आ रही है, इसके बारे में सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है और इसमें कितनी सफलता उसे मिली है? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें केवल इतना ही कहा है कि इस प्रकार की जो दैवी आपदाएं आ रही हैं उसके लिए जल संसाधन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान आदि नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसे उपायों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह प्रयास कब से प्रारंभ किया गया इस देश के अंदर और इसमें अब तक कितनी सफलता मिल सकी है? यह जो भविष्य में दैवी आपदाएं आएंगी, उस पर काबू पाया जा सके, नियंत्रण पाया जा सके, पूर्ण नियंत्रण पाया जा सके, इस तरह की क्या कोई उपलब्धि अब तक हुई है? भाग "ख" मेरे प्रश्न का यह होगा कि क्या सरकार का कोई इस तरह का लक्ष्य भी है कि किसी नियत अवधि तक इस प्रकार की दैवीय आपदाओं पर पूर्णतया नियंत्रण पाया जा सकेगा? इस प्रकार का क्या कोई आपका लक्ष्य है?

श्री सोमपाल: सभापति जी दैवी आपदाएं कोई एक प्रकार की नहीं है और अगर उनका कोई वर्गीकरण किया भी जाए तो वह एक बार जितने भयंकर रूप से आती हैं दूसरी बार उससे कम आ सकती हैं, ज्यादा आ सकती हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, कुछ संगठन, कुछ संस्थाएं, सरकारों के—केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के कुछ विभाग, मौसम विभाग और भारत सरकार का विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, यह इसके लिए हल खोज रहे हैं? तो हल खोजा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि अभी खोजना प्रारम्भ किया है, यह खोज तो सतत् चलती रहती है, पहले से चल रही है और यह सदा चलती भी रहेगी। जहां तक उनका यह प्रश्न है कि इन पर काबू कहां तक पाया जा सकता है, तो पूर्ण नियंत्रण प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि पर कभी भी नहीं पाया जा सकता। जहां तक इसमें सफलता का प्रश्न है, इसके लिए तीन-चार चरण हैं। पहले इन आपदाओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है—किस प्रकार की आती है, उनके लिए पूर्व चेतावनी कैसे दी जा सकती है, जो लोग उनसे प्रभावित होने वाले हैं या जो सम्पत्तियां हैं, उनके लिए क्या प्रबंध अग्रिम रूप से किए जा सकते हैं और

† सभा में यह प्रश्न श्री ईशदत्त यादव द्वारा पूछा गया

जब आपदा आ जाती है तो उससे होने वाली हानि को कैसे कम किया जा सकता है और उसके लिए जो राहत दी जाती है, चाहे भोजन के रूप में हो, दवाई के रूप में हो, परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के रूप में हो, उसके लिए मापदंड क्या है, इस तरह के सारे कायदे-कानून जिनको कोड्स कहते हैं, यह संहिता बनती रहती है और जब भी कोई आपदा नए रूप से आती है तब उन संहिताओं के शोधन का, संशोधन का कार्य भी चलता है। जहां तक अब तक हुई प्रगति का प्रश्न है, इसे किसी आंकड़े में या किसी भौतिक रूप में नापना संभव नहीं है। अक्सर यह देखा गया है 1954 से 1985 के आंकड़ों में कि लगभग एक हजार करोड़ रुपए की आर्थिक हानि हर वर्ष बाढ़ से होती है, कुछ वर्षों में इससे ज्यादा भी हानि हुई है और एक वर्ष तो ऐसा है जिसमें चार हजार छः सौ तीस करोड़ रुपए की हानि हुई, वर्ष 1988 में, और यह अपने आप में एक रिकार्ड था। इसी प्रकार जन-हानि भी प्रायः होती है। ....(व्यवधान)....

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: ऐसे तो कोई सवाल ही नहीं पूछ सकेगा क्योंकि मंत्री महोदय इतनी लम्बी स्पीच दे रहे हैं। मंत्री महोदय कृपा करके संक्षिप्त जवाब दें ताकि और लोग भी सवाल पूछ सकें।

श्री सोमपाल: सभापति जी मेरी यह कठिनाई है कि जितनी सूचना माननीय सदस्य ने पूछी है, उतनी सूचना ....(व्यवधान)....

श्री ईश दत्त यादव: सभापति जी, मैंने संक्षेप में सूचना मांगी है कि क्या इस पर कुछ नियंत्रण अब तक पाया जा सका है? जो अनुसंधान या प्रयास हुए हैं, उनसे कुछ नियंत्रण पाया जा सका है या नहीं? मेरा तो यह संक्षिप्त प्रश्न है।

श्री सोमपाल: मैंने कहा है कि कुछ नियंत्रण पाया जा सका है और कुछ नहीं पाया जा सका है और आगे भी ऐसा ही रहेगा।

श्री ईश दत्त यादव: धान्यवर सभापति जी, पूरी दुनिया में दैवी आपदा आती है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जिसके लिए पूरी दुनिया में 8 अक्तूबर की तारीख निर्धारित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दैवी आपदा दिवस इस देश में भी मनाया जा रहा है 8 अक्तूबर को और गत तीन वर्षों में क्या-क्या प्रयास किए गए और कैसे इसको सम्पन्न किया गया?

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, 1990 का जो चालू दशक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय आपदा दशक का नाम दिया गया है और इसके उपलक्ष्य में भारत में भी कुछ सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निबटने के लिए जो पहले से नियमावली बनी हुई है, जो कोड और संहिताएं पहले निर्मित हो चुकी हैं, उनमें जहां-जहां सुधार की संभावनाएं हों, वे सुधार किए जाएं और लोगों को, जो प्रायः इससे प्रभावित होते हैं, उनको भी इसके संबंध में जानकारी दी जाए। तो इस प्रकार से सम्मेलन यहां भी किए गए हैं और 13 या 14 सेमिनार भारत में किए जा चुके हैं। यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और अक्टूबर महीने के दूसरे बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन इस दशक में किया जाता रहा है और इस दशक के अंत तक इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: उनका बेसिक सवाल यह है कि इस साल होगा या नहीं?

श्री सोमपाल: जी हां, होगा।

श्री सभापति: मंत्री जी, उनको जवाब मिल गया है, अब आप बैठ जाइए।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, it is a known fact that in the past more emphasis was laid on relief and rehabilitation work, rather than on finding out a permanent solution to environmental disasters and natural calamities in the country. Sir, I will refer to only one data and that is with regard to Assam. In Assam there had been an annual loss of life and property to the tune of Rs. 3000 crores every year and the amount invested for relief and rehabilitation work had been only Rs. 500 crores every year. It amounts to an accumulated loss of about Rs. 1,50,000 crores in the last fifty years. Sir, I want to know precisely from the Minister—as our agencies have failed to find out a scientific solution to this—whether the Government is planning to involve international agencies, including various wings of the United Nations to study this problem and find out a solution to this. Thank you.

SHRI SOMPAL: Mr. Chairman, Sir, this is a continuous process and the Government of India and its agencies are in continuous contact with international agencies to update themselves and to acquire infrastructure for forewarning about floods, cyclones, earthquakes and droughts, and this will continue to be so.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Mr. Chairman, Sir, as the hon. Minister in his reply has said that this Government is giving internet facilities to local STD booths, and it is *daiva-durvipatti*. I think, this statement is not correct.

Whether the Minister is aware of the fact that Orissa is a flood and cyclone prone State? Is he also aware of the fact that about 4000 persons died in the last heat wave in Orissa? However, as per the Government official report the number of persons died were around 1200 while, in fact, the number of persons died were about 4000. Whether the Prime Minister or the Minister has visited Orissa after the heat wave? Whether any compensation has been paid to the families of these 4000 deceased persons by the Govt. of India as it is paid in the case of cyclone, flood accident and fire accident? Whether the Government is also trying to find out the cause of heat wave in Orissa where about 4000 poor workers died in the last heat wave?

SHRI SOMPAL: Sir, in such matters the Central Government has to depend on the reports by the State Governments. Central teams are sent only when they are asked for by the State Governments. We did not receive any such memorandum from the Government of Orissa for dispatching a Central team there. In the absence of such a memorandum no team was dispatched there. This is the arrangement so far as...*(Interruptions)*...

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, about 4000 persons have died there and the Minister wants a report from the State Government...*(Interruptions)*...I am sure the State Govt has sent its report. Sir, it is a very dangerous thing...*(Interruptions)*...It means if the State Government will not do so, they will not...*(Interruptions)*... Sir, I want an answer from the hon. Prime Minister...*(Interruptions)*... In my State about 4000 persons have died and the Minister wants a report from the State Government. I request that the hon. Prime Minister must give an answer to this question. ...*(Interruptions)*...

SHRI SURESH PACHOURI: We want a half-an-hour discussion on this...*(Interruptions)*... We want a half-an-hour discussion on this...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down...*(Interruptions)*...You can give a notice for a half-an-hour discussion...*(Interruptions)*...The Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Minimum support price for Paddy

*321.SHRI YADLAPATI VENKAT RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the minimum support price for paddy by atleast Rs. 75/- per quintal as was given in case of wheat;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal to increase the Minimum Support Price (MSP) of paddy already announced as it is a quite remunerative.